

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद
(राकेश कुमार आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :- 15/2019
दायर दिनांक :- 08/04/2019
निर्णय दिनांक :- 29/11/2019

अनवान

श्री मोहन पिता माला कुमावत निवासी नारायणगंज (ओडा) तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

—अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा, जिला राजसमन्द

— रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार रेलमगरा प्रकरण संख्या 153/2016 ना. क.
निर्णय दिनांक 07.03.2019

उपस्थित :-

- 1—श्री सम्पतलाल लढ्ढा, अधिवक्ता अपीलान्ट
- 2—श्री कैलाश बोल्या, राजकीय अधिवक्ता

—:: निर्णय ::—

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं । अपीलांट के विरुद्ध राजस्व ग्राम नारायणगंज पटवार हल्का ओडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द में स्थित आराजी संख्या 1983/1 रकबा 305-01 बीघा भूमि किस्म बिलानाम नदी पर 4.00 बिघा भूमि पर अतिक्रमण कर लिये जाने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर अतिक्रमण को भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर विवादित भूमि से अतिक्रमण को बेदखल करने एवं भूमि पर अतिक्रमण मानते हुये लगान 10 रुपये का 50 गुणा शास्ति रुपये 500/- एवं फसल निलामी राशी 2000/- रुपये आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का निर्णय दिनांक 07.03.2019 को पारित किया । अधिनस्थ न्यायालय के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है ।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्ट को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी ।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट द्वारा राजस्व ग्राम नारायणगंज पटवार हल्का ओडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द में स्थित खसरा संख्या



W

1983/1 रकबा 305-01 बीघा भूमि किस्म बिलानाम नदी पर 4.00 बीघा भूमि पर प्रार्थी का बहुत पुराना कब्जा है, राजस्व रेकार्ड में गलत रूपेण बिलानाम नदी दर्ज है, वहां पर नदी का बहाव क्षेत्र नहीं है तथा नदी का पानी कभी भी वहां तक नहीं आया है, अपीलार्थी का कब्जा पुराना होना प्रस्तुत की गई पी. 14 की रिपोर्ट से पूर्णत साबित है। अवर न्यायालय के समक्ष प्रार्थना भी की गई कि वादग्रस्त स्थल पर पानी नहीं आता है तथा किस्म परिवर्तन करना जरूरी है, जिसके लिये जिला कलक्टर महोदय राजसमंद के यहां रेफरेन्स हेतु प्रेषित किया जाना चाहिये, किन्तु अवर न्यायालय के अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही प्रेषित करने के बजाय फेसल कर दी व अपीलार्थी का समुचित प्रतिरक्षा का अवसर नहीं मिला है। अपीलार्थी ने जवाब में स्पष्ट लिखा है कि मौका स्थिति स्थल निरीक्षण रिपोर्ट हमारी उपस्थिति में बनाई जावे, ताकि मौके की वास्तविक स्थिति रेकार्ड पर आ सके, किन्तु अपीलार्थी की मांग पर ध्यान नहीं दिया गया। अपीलार्थी ने स्वयं व गवाहों के बयान करने हेतु भी निवेदन किया, किन्तु कोई अवसर नहीं दिया गया, जिससे न्याय की हानि हुई है। वर्ष 2016 में बहुत अधिक बरसात हुई, रेलमगरा क्षेत्र में बाढ़ भी आई, नन्दसमन्द बांध के सभी गेट से पानी छोड़ा गया, किन्तु वह पानी भी वादग्रस्त स्थल से 100 फीट की दूरी से भी अधिक दूरी से निकला है, इतने अधिक पानी में भी अपीलार्थी के कब्जाशुदा वादग्रस्त क्षेत्र में नहीं आया तो जांच वह भी गहन जांच जरूरी है, कि वास्तव में रेकार्ड में "किस्म नदी" सही भी है, या केवल रेकार्ड पर त्रुटि से ऐसा अंकन हुआ है पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से वादग्रस्त स्थल पर पानी नहीं आया तो बेदखली का औचित्य क्या है, इससे व्यक्तिगत क्षति के साथ साथ राष्ट्रीय आय का भी नुकसान होगा। बिलानाम जमीन को अपीलान्ट ने लाखों रुपये खर्च कर काबिल कास्त बनाया है। पास में ही कुंवा खोदा गया है, जिससे हमारे खेतों में इंजिन के जरिये फसलों की पिलाई की जाती है, तथा वर्तमान में हमने ज्वार व मक्की की फसल बुवाई है, जो फसल भी मौके पर विद्यमान है। मौके के फोटो से भी स्पष्ट है, जिससे हमारे उक्त कथनों की पूर्ण रूप से पुष्टि होती है। जिसकी ताईद जिन्सवारी का अहम दस्तावेज भी कहता है कि अपीलान्ट ने जमीन में काफी समय से उपजाऊ योग्य बना कर कास्त की है, गलती से रेकार्ड में किस्म नदी अंकित होने से हमारे खातेदारी होने से रह गई हैं इस संबंध में जांच रिपोर्ट मंगवा ली जावे कि हमारी जमीन में इस वर्ष भी नदी का पानी आया नहीं, कितने वर्षों से पानी हमारे खेतों में नहीं आया। जब नदी वादग्रस्त खेत में से गुजर ही नहीं रही है तो किस्म नदी के अंकन के आधार पर हमारे विरुद्ध नाजायज रूप से बेदखली की कार्यवाही उचित नहीं है। इस प्रकरण को जिला कलक्टर/ रेवेन्यु बोर्ड को भेजा जाना चाहिये कि बिलानाम जमीन पर 50 वर्षों से भी अधिक समय में कभी भी नदी का पानी या बहाव क्षेत्र हमारे कब्जेशुदा वादग्रस्त खेत में नहीं आया, तब क्या वादग्रस्त क्षेत्र को नदी माना जावेगा? यदि नहीं मानते हैं तो हमारा मामला नियमन योग्य बनता है। क्योंकि हमारा कब्जा काफी वर्षों पुराना है तथा जमीन को हमने लाखों रुपये खर्च कर आबाद कर काबिल कास्त किया है। मौके पर अपीलान्ट ने कुंवा का निर्माण भी करवाया है, जो नियमन हो चुका है। केवल वादग्रस्त भूमि नियमन होनी शेष है, जिससे उक्त सम्पूर्ण मामला नियमन कमेटी में भेजे जाने योग्य होकर उक्त भूमि नियमन की श्रेणी में आती है। जिससे बेदखली की कार्यवाही की जानी अनुचित है। वर्तमान में किस्म परिवर्तन होने में समय लगता है एवं अपीलार्थी की भूमि तक नदी का पानी किसी समय आता भी है तो अपीलार्थी स्वतः खेती नहीं कर पायेगा, किन्तु बेदखली की कार्यवाही से गरीब अपीलार्थी द्वारा कड़ी मेहनत से बनाई जमीन से बेदखली पर अपीलार्थी बर्बाद हो जावेगा। अपीलान्ट के पास अन्य कोई जमीन नहीं है, अपीलान्ट अकृषक की श्रेणी में आता है तथा अपीलान्ट को बेदखल किये जाने पर अपीलान्ट बर्बाद हो जावेगा, अपीलान्ट की आजीविका का एक मात्र जरिया वादग्रस्त कृषि भूमि ही है। खेत नष्ट क्षतिग्रस्त कर दिये जाने पर अपीलान्ट को भारी नुकसान होगा, अपूर्णाय क्षति होगी तथा भारी विवाद बढ़ जावेगा। जिसकी पूर्ति किसी भी रूप में नहीं की जा सकती। न्यायालय



तहसीलदार द्वारा अतिक्रिमी के विरुद्ध जो निर्णय व कार्यवाही की गई हैं, वह उचित प्रतीत नहीं होती है। न्यायालय तहसीलदार द्वारा की गयी सारी कार्यवाही गलत एवं विधिविरुद्ध है और अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रेलमगरा का आदेश खारिज फरमाया जावे ।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया है कि राजस्व ग्राम नारायणगंज तहसील रेलमगरा की आराजी नम्बर 1983/1 रकबा 305.01 बीघा भूमि किस्म बिलानाम नदी मे से 4.00 बीघा भूमि पर अतिक्रिमी द्वारा नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण किया गया । अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पर्याप्त सुनवाई एवं दस्तावेज पेश करने का अवसर दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में हल्का पटवारी से अतिक्रिमी का कब्जा काश्त और मौके की रिपोर्ट चाही गई । पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट मय मौका पर्चा ,जमाबन्दी मय ट्रेस प्रस्तुत कि जो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर मौजूद है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में बताया हैं कि अपीलान्ट श्री मोहन पिता माला कुमावत का आराजी नम्बर 1983/1 रकबा 305.01 बीघा भूमि किस्म बिलानाम नदी में से 4.00 बीघा भूमि पर विपक्षी का कब्जा चला आ रहा है। विपक्षी का कब्जा काफी पुराना है किन्तु अतिक्रमणसुदा भूमि बिलानाम नदी दर्ज है। जो किसी भी प्रकार से नियमन योग्य नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में आती है। इसके साथ ही D.B. Civil Writ Petition No. 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02-08-04 से भी सम्बन्धित है। जिससे विपक्षी के नाम किसी भी सुरत में भी भूमि नियमन योग्य नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रिमी के विरुद्ध जो निर्णय व कार्यवाही की गई हैं, वह उचित प्रतीत होती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी सारी कार्यवाही विधिसम्मत है और अधिनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जावे । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावे ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । बहस पर मनन किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलान्ट द्वारा राजस्व ग्राम नारायणगंज तहसील रेलमगरा की आराजी नम्बर 1983/1 रकबा 305.01 बीघा किस्म बिलानाम नदी भूमि में से 4.00 बीघा भूमि पर अतिक्रिमी द्वारा नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण किया गया है। विवादित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में आती है। इसके साथ ही D.B. Civil Writ Petition No. 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02-08-04 से भी सम्बन्धित होने से नियमन एवं आवंटन नहीं की जा सकती । अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रिमी के विरुद्ध की गई कार्यवाही बेदखल व शास्ति 500/-रुपये एवं फसल निलामी राशि 2000/- रुपये आरोपित करने के आदेश से मैं सन्तुष्ट हूँ । अधिनस्थ न्यायालय के आदेश में मैं किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता हूँ। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जाता हैं । अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।



(रकेश कुमार)
अति० जिला कलेक्टर
राजसमन्द